भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2498

(सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

उत्तर प्रदेश के मेरठ और हापुड़ जिलों में सीएसआर का उचित व्यय

2498. श्री अरुण गोविलः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की प्रत्येक जिले में सीएसआर राशि के उचित व्यय के लिए कोई कार्य-योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ और हापुड़ जिलों में उचित सीएसआर व्यय कब तक होने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है या जिसका कारोबार 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है या तत्काल पूर्व के वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, यह सुनिश्चित करेगी कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में तत्काल तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% व्यय करे। सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हे निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार है। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुमोदित राशि सौंपे गए कार्यकलाप (कार्यकलापों) पर व्यय की गई है। यदि कोई राशि व्यय नहीं की जाती है तो ऐसी राशि निर्धारित समय सीमा में अनुसूची VII में नामित निधि (निधिओं) में अंतरित की जाएगी। सरकार कोई निदेश जारी नहीं करती है कि कंपनी किस कार्यकलाप या क्षेत्र पर व्यय करेगी।

*****